Charges against previous Administration of Delhi

4209. **SHRI KANWAR LAL GUPTA:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received charge-sheet against the outgoing Congress administration of Delhi in the last 4 months;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken by the Government over each complaint?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Two memoranda containing charges against the erstwhile Chief Executive Councillor, Executive Councillors and officers of various agencies of Delhi such as the New Delhi Municipal Committee, the Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Development Authority, the Delhi Transport Corporation, the Delhi Small Industries Development Corporation, the Delhi Electric Supply Undertaking and various department of Delhi Administration have been received by the Government. The charges are being enquired into.

Purchases by Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, D.E.S.U., D.M.C. and N.D.M.C. from Maruti

4210. **SHRI KANWAR LAL GUPTA:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of purchases made by Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, D.E.S.U., D.M.C. and N.D.M.C. from Maruti Ltd., Maruti Heavy Vehicles and Maruti Technicals in the last three years;

(b) what were the irregularities in those purchases;

(c) what action has been taken or proposed to be taken by the Government against concerned officers and their names and designation;

(d) whether any case has been registered against any body or company; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) According to information received, the following purchases were made

(i) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking purchased 96,350 Kgs. of Quick Floc Polymix from M/s. Maruti Technical Services (Pvt.) Ltd.

(ii) The Delhi Electric Supply Undertaking purchased 600 Kgs. of Quick Floc Polymix from M/s. Maruti Technical Services Pvt. Ltd.

(iii) The Delhi Municipal Corporation purchased 100 Kgs. of Quick Floc Polymix from M/s. Maruti Technical Services Pvt. Ltd.

(iv) The Delhi Municipal Corporation purchased 3 Maruti brand road rollers from M/s. Jallan Modi Automobiles, the selling agents' of Maruti Heavy Vehicles (P) Ltd.

(v) The New Delhi Municipal Committee purchased 3 Maruti brand road rollers and some spare parts from M/s. Jalan Modi Automobiles, the selling agents of Maruti Heavy Vehicles (P) Ltd.

(b) to (e). The Central Bureau of Investigation registered a case regarding the purchase of Quick Floc Polymix by Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking from Maruti Technical Services (Private) Limited on 24-5-1977. After completion of investigation, a charge-sheet has been filed by the Central Bureau of Investigation in the Court of the Special Judge, Delhi on 14-7-1977 against Shri Sanjay Gandhi and Shri R. C. Singh under Section 120-B IPC read with Section 5 of Prevention of

Corruption Act and Section 109 IPC. Some irregularities in the purcase of Quick Floc Polymix by Delhi Electric Supply Undertaking were also found by the Central Bureau of Investigation. No investigations have been conducted in other cases so far.

आपात स्थिति के दौरान आन्ध्र प्रदेश में व्यक्तियों को परेशान किया जाना

4211. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1977 के "डैकन हेरल्ड" मे प्रकाशित श्री जी० सुन्दरैया के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमे कहां गया है कि आपात् स्थिति के दौरान आंध्र प्रदेश मे लगभग 350 व्यक्तियो को मौत का शिकार होना पड़ा, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) . (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार आरोप निराधार है । आपातस्थिति के दौरान पुलिस और उग्रपथियों के बीच 30 सशस्त्र मुठभेड़े हुई थी, जिनमे 34 उग्रपन्थी मारे गये थे । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री वी० भार्गव की अध्यक्षता में एक जांच आयोग ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जा चुका है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती

4212. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय इंजीनियरी सेवा आदि जैसी विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक कितने प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उक्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये और भर्ती किए गये कुल उम्मीदवारों में उनकी प्रतिशता क्या है ; और

(ग) क्या उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता से अनुसूचित जातियों के कम उम्मीदवार भर्ती किये गये है और यदि हां तो आरक्षण की प्रतिशतता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) तीन अखिल भारतीय सेवाओं, अर्थात् भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता सीधी भर्ती के पदों को क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत है । भारतीय इंजीनियरी सेवा का अभी तक गठन नहीं किया गया है ।

(ख) भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता :